दूरभाषः 23468306/07

फैक्सः 23702440

Directoriipa9@gmail.com

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,

नई दिल्ली

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2025

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2025 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार राशि निम्नवत् हैः

प्रथम पुरस्कार	रूपये 10,000/-
द्वितीय पुरस्कार	रूपये 7,000/-
तृतीय पुरस्कार	रूपये 5,000/-

जिस प्रतियोगी को इस प्रतियोगिता में एक बार पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वह प्रतियोगी दुबारा उसी श्रेणी या उससे निम्न श्रेणी के किसी पुरस्कार का हकदार नहीं होगा। निबंधों के संयुक्त लेखन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा संयुक्त रूप से लेखकों द्वारा लिखित किसी भी निबंध पर प्रतियोगिता के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

(i) कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग

(ii) सोशल मीडिया चुनौतियाँ और अवसर

(iii) जीवन की सरलता

निबंध लेखकों से अपनी प्रविष्टियों में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना अपेक्षित हैः

विषय (1) : कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग

निबंध में मुख्यतः निम्न विशद् बिंदु शामिल किए जाने चाहिएः

1. **परिचय**

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वर्तमान तेजी से तकनीकी विकास के युग में एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभरी है, जो मानव जीवन और कार्य के कई पहलुओं को परिवर्तित कर रही है। पहले जिन

चुनौतियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, अब उन्हें अद्भुत आसानी से हल किया जा रहा है, क्योंकि एआई प्रौद्योगिकियाँ रोजमर्रा की वास्तविकता में अधिक से अधिक समाहित होती जा रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में प्रगति अब विज्ञान काल्पनिकता के क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गई है यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। यह शासन में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है, जो सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक सहभागिता और नीति प्रभावशीलता में सुधार के लिए विशाल संभावनाओं की पेशकश कर रही है। दुनिया भर की सरकारें, भारत सहित, स्थायी विकास प्राप्त करने, मानव त्रुटियों को कम करने, सेवा वितरण को बढ़ाने और गतिशील सामाजिक जरूरतों के प्रति प्रभावकारी रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए एआई को अपने मुख्य कार्यों में बढ़ते हुए समाहित कर रही हैं। हालाँकि, इसके परिवर्तनकारी संभावनाओं के साथ डेटा गोपनीयता, जवाबदेही, नैतिक उपयोग और समान पहुंच के संबंध में चिंताएँ भी हैं।

2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार

एआई बाजार वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार कर रहा है। ग्रैंड व्यू रिसर्च (2024) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग के 2023 में 196.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, और इसके 2024 और 2030 के बीच 36.6ः की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है। 2030 तक, दुनिया भर में बाजार 1.8 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक के पैमाने तक बढ़ने की उम्मीद है, जो सभी उद्योगों में अनुसंधान, तैनाती और निवेश में तेज वृद्धि को दर्शाता है। बड़े डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, परिष्कृत एल्गोरिदम और कभी–कभी अधिक शक्तिशाली कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे का संयोजन इस विस्तार को चला रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पारिस्थिति का तंत्र तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में पर्याप्त वृद्धि से चिह्नित है। भारत ने एआई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, सामाजिक विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वजनिक लाभ के लिए एआई का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अपनी दृष्टि के साथ संरेखण में "भारत में एआई बनाने" और "भारत के लिए एआई कार्यान्वयन" के तहत, सरकार ने ₹10,371.92 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश के साथ पूरे देश में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। ये उन्नति देश को विकसित देशों, जिसमें G7 और G20 के सदस्य शामिल हैं, के साथ विशिष्ट स्थान पर स्थापित कर रही हैं। इस वर्ष 18 मार्च को, भारत और अमेरिका के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल को इंदो–यू.एस. साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ((IUSSTF) द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य ज्ञान विनिमय, शोध और विकास के अवसरों, और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक गतिशील प्लेटफॉर्म स्थापित करना है। वैश्विक स्तर पर, संज्ञानात्मक और एआई समाधानों में निवेश की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है कि यह 50.1% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़कर 2021 तक USD 57.6 बिलियन तक पहुँच जाएगा, जो कई उद्योगों में महत्वपूर्ण अपनाने द्वारा संचालित है।

3. पृष्ठभूमि

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सैद्धांतिक और तकनीकी आधार मुख्यतः पिछले 70 वर्षों में कंप्यूटर वैज्ञानिकों जैसे कि एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिंस्की और जॉन मैकार्थी द्वारा बनाए गए थे। एआई कोई नया घटना नहीं है। एआई पहले से ही अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों और कई सरकारों में मौजूद है। अब हम एआई के गुणनात्मक युग के कगार पर हैं, क्योंकि व्यवसाय बड़ी मात्रा में डेटा में छिपी हुई मूल्य को अनलॉक करना सीख रहे हैं, जो लगभग असीमित कंप्यूटर शक्ति और घटते डेटा भंडारण लागत के कारण है।

AI बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है ताकि ऐसे अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकें जो साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण और रणनीतिक योजना में मदद करें, जिससे अधिक सूचित और प्रभावी निर्णय प्राप्त हों। AI जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा–प्रेरित निर्णय लेने को रूपांतरित कर रहा है ताकि विशाल डेटा की मात्रा को तेजी से और कुशलता से मूल्यांकित किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) छिपे हुए पैटर्न, संबंध और प्रवृत्तियों का पता लगा सकता है जिन्हें मानव विश्लेषक शायद मिस कर दें, दोनों संरचित और असंरचित डेटा का विश्लेषण करके। इस कौशल का उपयोग करके, संगठन बेहतर सूचित निर्णय ले सकते हैं जो अंतर्दृष्टि पर निर्भर करते हैं, न कि अपर्याप्त ज्ञान पर।

इसके अतिरिक्त, एआई निर्णय समय सीमा को तेज करता है और डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण जैसी दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं को स्वचालित करके दक्षता बढ़ाता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में वृद्धि होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)–संचालित भविष्यवाणी विश्लेषण भविष्य के पैटर्न और परिणामों की भविष्यवाणी करता है, जो जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक योजना का समर्थन करता है। वास्तविक समय के निर्णय समर्थन प्रणालियों के माध्यम से तेजी से अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है, जिससे बदलती परिस्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रियाएं संभव होती हैं। सुशासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI4 Sushaasan) का ध्यान अच्छे शासन के लिए एआई का विकास और अनुप्रयोग पर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ अच्छे शासन और सरकारी नीतियों के लागू करने के लिए किया जाए ताकि भारत को हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन आर्थिक लक्ष्य के करीब लाया जा सके। (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की खोज सरकारों द्वारा दुनिया भर में विभिन्न उद्देश्यों के लिए तेजी से की जा रही है क्योंकि यह दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।

4. भारत का नया एआई स्टैक और इंडिया एआई मिशन: विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में AI एक्शन समिट में कहा, "भारत पहले से ही हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा, और यहाँ तक कि हमारे समाज को फिर से आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है।" उनके शब्द इस बात का प्रतिबिंब हैं कि देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के भविष्य को आकार देने में बढ़ती हुई नेतृत्व कर रहा है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जो एक मील का पत्थर पहल है जिसे भारत को एआई विकास और तैनाती के लिए वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। पांच वर्षों में 10,371.92 करोड़ रुपये के कैबिनेट द्वारा अनुमोदित बजट के साथ, यह मिशन एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के रूप में अनुरूप किया गया है जो भारत के एआई पारिस्थिति की तंत्र में प्रणालीगत अंतर को मिटायेगा और सुनिश्चित करेगा कि एआई के लाभ समाज के सभी स्तरों तक पहुँचें।

5. भारत एआई मिशन: रणनीतिक स्तंभ और कार्यान्वयन

इंडिया एआई मिशन का लक्ष्य एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो एआई नवाचार को बढ़ावा देता है, कंप्यूटिंग एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाता है, डेटा गुणवत्ता को सुधारता है, स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास करता है, शीर्ष एआई प्रतिभाओं को आकर्षित करता है, उद्योग सहयोग को सक्षम बनाता है, स्टार्टअप के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करता है, सामाजिक रूप से प्रभावशाली एआई

परियोजनाओं को सुनिश्चित करता है, और नैतिक एआई को बढ़ावा देता है। यह मिशन भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र की जिम्मेदार और समावेशी वृद्धि को निम्नलिखित सात स्तंभों के माध्यम से संचालित करता है।

• इंडिया एआई कंप्यूटर

• इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर (IAIC)

• इंडिया एआई डेटासेट्स प्लेटफॉर्म

• इंडिया एआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव

• इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स

• इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग

• सुरक्षित और विश्वसनीय AI

ये स्तंभ एक मजबूत, समावेशी और नैतिक एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

विकासात्मक दृष्टि: समावेशी, जिम्मेदार और संप्रभु एआई–भारत का एआई दृष्टिकोण सार्वजनिक भलाई के लिए एआई पर केंद्रित है, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में। ऐसे अनुप्रयोग जैसे:

• जलवायु जोखिमों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

• दूरस्थ एआई–सहायता प्राप्त निदान

• क्षेत्रीय भाषाओं के लिए मशीन अनुवाद ... डिजिटलीकरण के अंतर को पाटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह मिशन भारत के भाषा मॉडलों को प्रमुखता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन 90 भारतीयों तक पहुंच हो जो इंग्लिश में धाराप्रवाह नहीं हैं। नैतिक चिंताएँ–जैसे कि पूर्वाग्रह, निगरानी और गलत जानकारी–को इस स्टैक की शासन परत के माध्यम से सक्रिय रूप से संबोधित किया जा रहा है।

6. संबोधित करने के लिए चुनौतियाँ

इसके परिवर्तनकारी क्षमता के बावजूद, भारत में एआई को अपनाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

- नैतिक चिंताएँ: पूर्वाग्रह, मानव पर्यवेक्षण की कमी
- गंभीर सोच में गिरावट: एआई उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता
- पर्यावरणीय प्रभाव: डेटा केंद्रों की उच्च ऊर्जा खपत
- श्रमिक विस्थापन: विशेष रूप से कम कुशल क्षेत्रों में

- कार्बन फुटप्रिंट: टिकाऊ एआई की आवश्यकता
- डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा: नियामकीय खामियां
- ओवरयूज और समय से पहले तैनाती: अप्रभावी मॉडलों का जोखिम
- कौशल अंतर: AI प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी
- बुनियादी ढांचे की कमी: अपर्याप्त क्लाउड और कंप्यूटिंग संसाधन
- डेटा पहुंच और गुणवत्ता की समस्याएँ: टुकड़ों में बंटी और अपर्याप्त एनोटेटेड डेटासेट्स

7. **निष्कर्ष**

निष्कर्ष के रूप में, AI विकास के उभरते क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से लेकर जलवायु कार्रवाई और शासन तक, सभी क्षेत्रों में विशाल परिवर्तनकारी क्षमता है। हालांकि, इन प्रौद्योगिकियों की जिम्मेदार उन्नति के लिए नैतिक शासन, पारदर्शिता और समावेशिता पर एक जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को संयुक्त रूप से नियामक ढांचे बनाने, अंतःविषय अनुसंधान का समर्थन करने और डिजिटल अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि AI के लाभों को समान रूप से वितरित किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की तैयारी को मजबूत करना, ओपन–सोर्स सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना संभावित जोखिमों का सामना करने और टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए AI की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

निबंध लेखन के लिए फोकस के प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. सार्वजनिक सेवाएँ और शासन
2. नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया
3. सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा
4. स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएँ
5. परिवहन और अवसंरचना
6. साइबर सुरक्षा और खतरे का विश्लेषण
7. पर्यावरण निगरानी, टिकाऊपन और आपदा प्रबंधन
8. शिक्षा और कार्यबल विकास
9. कानूनी अनुसंधान और न्यायपालिका
10. सार्वजनिक शिकायत निवारण
11. कृषि और खाद्य सुरक्षा
12. बैंकिंग और ग्रामीण वित्तीय सेवाएँ
13. साफ पानी और स्वच्छता
14. विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स

15. कानून प्रवर्तन के लिए सोशल मीडिया निगरानी
16. UNSDG – संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य
17. डेटा गोपनीयता और सुरक्षारू नियामक अंतर
18. कार्बन फुटप्रिंट: टिकाऊ एआई की आवश्यकता
19. नैतिक ढांचा और शासन।

विषय (2) : सोशल मीडिया चुनौतियाँ और अवसर

जिस तरीके से बेनेडिक्ट एंडरसन ने 90 के दशक में "कल्पित समुदायों" को लिखा है, यह सामाजिक मीडिया की लोकप्रियता और उपयोग के द्वारा पूरी तरह से सही साबित हुआ है, जहां लोग एक–दूसरे के साथ वास्तविक संपर्क में नहीं होने के बावजूद, "तत्कालता" के साथ संवाद कर सकते हैं और एक–दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह राष्ट्रों और उनकी जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग एक–दूसरे से काफी दूर रहते हैं, विभिन्न स्थानों पर रहते और काम करते हैं, जबकि वे संवाद के साधनों, परिवहन और अब सामाजिक मीडिया के माध्यम से एक–दूसरे से बातचीत करते हैं, जो नागरिक केंद्रित कनेक्टिविटी का एक और तरीका है।

सोशल मीडिया थीम के दिशा–निर्देश और प्रारूप निम्नलिखित हो सकते हैं और जिनका प्रतियोगियों को पालन करना आवश्यक है। हम बाद में कथा और निबंध के पाठ के वास्तविक विवरण और तथ्यों में गहराई से जाएंगे, लेकिन आइए यहां उल्लेखित निबंध थीम के लिए एक सामूहिक प्रयास के लिए समझौता करें।

निम्नलिखित क्रम निबंध के लिए सामान्य दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकता है:

1.) **सोशल मीडिया का सिद्धांत**

एक ऐसे विश्व और राष्ट्रों के समुदाय में, जहाँ लोग एक दूरस्थ लेकिन उत्सुकता से जुड़े हुए संसार में जीवित हैं, लोग और एजेंसियाँ एक–दूसरे से अमूर्तताओं के क्षेत्र में संबंधित होती हैं, जहाँ दूर के रिश्तेदारों और एजेंसियों के संचार विशिष्ट रूप से सार्वजनिक और निर्बाध रूप से वैश्विक प्रचार और संचार के मैट्रिक्स पर हो सकते हैं। यह सत्तर के दशक में पेंटागॉन था जिसने "इंट्रानेट" के अवधारणा की शुरुआत की, जिसे बाद में बाकी सरकारी एजेंसियों और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा प्रतिकृत किया गया ताकि वे एक दोषरहित तरीके से जुड़ सकें और संवाद कर सकें। लोगों को सशक्त करने के लिए, आज की सरकार सोशल मीडिया का उपयोग कर रही है ताकि रेजिमेंटल योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके और नागरिकों से समय पर और उपयुक्त फीडबैक प्राप्त किया जा सके, जिससे सरकार अपनी कार्यप्रणाली को सुधार सके।

2.) लोग भाग लेना और राष्ट्रीय और आधिकारिक संचार की "चल रही चीजों" का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रकाशनीय उपस्थिति की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जो कि एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे पोर्टल लोगों के लिए सुविधाजनक बनाते हैं जिनके पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुँच नहीं है। इस प्रकार, स्वयं को अर्थपूर्ण तरीके से व्यक्त करने और अपने व्यक्तिगत विचारों और व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए, नागरिकों को एक बाहरी विश्व में पहुँच की आवश्यकता होती है जहाँ वे कह

सकते हैं कि विरोधी विचारों और धारणाओं का आदान–प्रदान कर सकें कि ट्रंप के शुल्क तंत्र बाकी राष्ट्रों और बड़ी दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए चुनौती कैसे बन रहा है।

3.) असहमतिपूर्ण विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय आजकल सोशल मीडिया के कामकाज के संदर्भ में आम बात बन गए हैं। राजनीतिक और वैचारिक रूप से सोशल मीडिया पोर्टल कभी–कभी आधुनिक दिन के 'अखाड़ों' में तब्दील हो जाते हैं, जहाँ प्रशंसकों और समर्थकों की संगठित सेनाएँ सोशल मीडिया पर एक–दूसरे से भिड़ती हैं, और ट्रॉलींग एक आम बात बन जाती है।

4.) सोशल मीडिया का निर्माण एक नया नवाचार है जहां एक देश के नागरिक जोर से चिल्ला सकते हैं, "हाँ! मैं प्रकाशित हुआ हूँ" जो जनता की आकांक्षाओं को प्रकट करता है। इस प्रकार, एक तरह से सोशल मीडिया का विषय भी खतरों से भरा हुआ है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की धाराएं अपनी सीमाएँ रखती हैं। एक तरह से, यह तर्क किया जा सकता है कि सोशल मीडिया ने लोकप्रिय विद्रोहों जैसे कि अरब वसंत को भी जीवंत किया है। जब ट्यूनीशिया में एक कपड़े के विक्रेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी आंदोलन की शुरुआत की।

5.) मीडिया परिदृश्य और तकनीकी कंपनियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का विविधता तेजी से विकसित हो रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। अब लोकतंत्र को यह आवश्यक है कि हम एक सामूहिक सीखने की प्रक्रिया में भाग लें ताकि ऑनलाइन सामग्री मॉडरेशन को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के साथ संगत किया जा सके। इस दृष्टिकोण से, ऐसी एक तंत्र की आवश्यकता है जो सामग्री के जन निगरानी को प्रभावी रूप से सुनिश्चित कर सके।

निम्नलिखित क्रम निबंध के लिए सामान्य दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकता है:

1.) "सोशल मीडिया" के रूप में जाने जाने वाले इस शब्द और घटना की परिभाषाएँ और परिचय।

2.) "सिमुलक्रा" शब्द की व्याख्या।

3.) सोशल मीडिया का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

4.) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश/ भूमि की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच का विवाद।

5.) सोशल मीडिया के वैश्विक नियामक मानदंड।

6.) भारत और अमेरिका के घरेलू और नियामक मानदंड सोशल मीडिया के लिए।

7.) वेब पर ट्रॉलिंग और मानहानिरू शांति, सद्भाव, शिष्टता और व्यवस्था के लिए एक चुनौती।

8.) राष्ट्रों, संस्थानों और भौगोलिक सीमाओं में भाषा कौशल, अभिव्यक्ति और इंटरएक्टिविटी में वृद्धि।

9.) लेखक की ओर से निष्कर्ष और सिफारिशें।

विषय (3) : जीवन की सरलता

परिचयः

आर्थिक विकास और भौतिक कल्याण, जो कि सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च) के संदर्भ में मापा जाता है, निश्चित रूप से एक देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन अकेले यह समाजों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, मुख्य चुनौती यह है कि विकास पर एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण बनाया जाए जो ऐसे पहलुओं को शामिल करता है जो आर्थिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं। विकास का अंतिम उद्देश्य नागरिकों के लिए समग्र जीवन परिस्थितियों में सुधार करना है, न कि केवल आर्थिक उत्पादन का विस्तार करना। जीवन की सुगमता एक देश के विकास का एक प्रमुख संकेतक है और नागरिकों के कल्याण में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सही अर्थ में अच्छा शासन तभी प्राप्त होता है जब नागरिक बिना देरी के सरकारी सेवाओं के लाभ प्राप्त करते हैं और विकास तभी सार्थक होता है जब यह दैनिक अनुभवों में सुधार करता है और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है।

जीवन की सरलता

अवधारणा और अर्थ "जीवन की सरलता" शब्द एक शहर, कस्बे या राष्ट्र में लोगों के सामान्य जीवन स्तर का वर्णन करता है। यह उन सभी पहलुओं का उल्लेख करता है जिन्हें व्यक्ति और समुदाय आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनुभव करते हैं। यह दर्शाता है कि लोग अपनी दैनिक जरूरतों और आकांक्षाओं को कितनी आसानी से और आराम से पूरा कर पा रहे हैं, जिसमें बुनियादी सेवाओं, सुरक्षा, गतिशीलता, वातावरण, रोजगार, आवास, और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों तक पहुंच शामिल है। यह वाक्यांश शहरी योजना, शासन, और नीति मूल्यांकन में उपयोग किया जा रहा है ताकि नागरिक–हितैषी वातावरण को बढ़ावा देने में प्रशासनिक उपायों की प्रभाविता का आकलन किया जा सके। जीवन की सरलता का मुख्य विचार यह है कि लोगों को बिना किसी अनावश्यक बोझ या बाधाओं के संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए।

यह एक समग्र अवधारणा है जो एक अच्छी तरह से कार्य करने वाले, समावेशी और टिकाऊ समाज को दर्शाती है। नागरिक एक सुचारू, परेशानी मुक्त और आरामदायक जीवन की उम्मीद करते हैं, जिसमें किसी कमी और संघर्ष का अभाव हो, और जो हमारे दैनिक जीवन में एक गरिमापूर्ण और सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित करता है। लेकिन, इसे प्राप्त करना कठिन है क्योंकि इसमें शासन संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और हर नागरिक की ओर से सहयोग और प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता होती है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी की प्रगति और सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। हालाँकि, कई मुद्दे अभी भी जारी हैं; नागरिकों के किसी भी सरकारी विभाग के साथ इंटरएक्शन के रूप में एक मुख्य बाधा अभी भी बनी हुई है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार के कारण, जो संस्थागत रूप से हो रहा है, नागरिकों का विश्वास पूरे शासन प्रणाली में कम हो गया है। यह न केवल नागरिक पर अनावश्यक लागत को लागू करता है बल्कि इसमें देरी, उत्पीड़न और अपमान भी शामिल होता है।

"जीवन की सरलता" मौजूदा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने कानूनी और शासन प्रणालियों में कई सुधार किए हैं। इनमें पुरानी कानूनों को समाप्त करना और पुरानी समस्याओं के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण के साथ कुछ शासन सुधारों को अपनाना शामिल है ताकि जीवन की आसानी सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने न केवल व्यापार करने की आसानी को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है बल्कि नागरिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जीवन की आसानी को सुधारने पर लगातार जोर दिया है। यह काम सरकारी हस्तक्षेप और बोझिल प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से संभव हुआ है। इसलिए कानूनों में सुधार, प्रशासनिक और न्यायिक सुधार, बुनियादी सुविधाओं में सुधार, सभी के लिए सेवाओं की उपलब्धता, हमारी शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का संपूर्ण सुधार नागरिकों के लिए जीवन की आसानी को सुधारने की पूर्वापेक्षाएँ हैं।

शहरों के लिए जीवन सुगमता सूचकांक

बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक व सामाजिक अवसरों की आकांक्षा के साथ अधिकाधिक भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अनुमान है कि 2050 तक भारत में विश्व की शहरी आबादी में 416 मिलियन शहरी निवासी जुड़ जाएँगे और यह कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 58ः होगा। इससे शहरों के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी होंगी। लोगों की बढ़ती संख्या और सीमित संसाधनों के साथ, शहरों को खुद को बनाए रखने और लोगों की भलाई और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कुशल प्रबंधन और योजना की आवश्यकता है। इसलिए, शहरीकरण में वृद्धि के साथ, जीवन की सुगमता को मापना और उसमें सुधार करना प्रासंगिक हो जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहर और राष्ट्र न केवल आकार में बढ़ें, बल्कि मानवीय सम्मान के साथ रहने योग्य स्थान भी बनें। भारत सरकार ने भारतीय शहरों को स्वस्थ, आकर्षक और टिकाऊ बनाने और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, हृदय, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई पहल की हैं।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा जनवरी 2018 में श्जीवन सुगमताश सूचकांक जारी किया गया था। इस सूचकांक का उद्देश्य शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के आधार पर व्यवस्थित रूप से स्वयं का आकलन करने में सहायता करना और उन्हें शहरी नियोजन एवं प्रबंधन के लिए 'परिणाम–आधारित' दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जीवन सुगमता ढाँचे का सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से गहरा संबंध है क्योंकि मूल्यांकन के संकेतक शहरी परिवेश में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण कई मानदंडों को शामिल करते हैं। इस सूचकांक का उद्देश्य तीन स्तंभों: जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता और स्थिरता, के आधार पर शहरों में रहने वाले नागरिकों के जीवन सुगमता को मापना है।

'जीवन सुगमता' सूचकांक के अंतर्गत जिन चार महत्वपूर्ण स्तंभों की जाँच की गई है, वे हैं – संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक, जो जीवन सुगमता को परिभाषित करने वाले व्यापक वैचारिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन सुगमता सूचकांक चार मानदंडों के आधार पर 111 शहरों में भारतीय निवासियों की भलाई का आकलन करता है: जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और निवासियों की धारणा सर्वेक्षण।

तदनुसार, निबंध लेखक एक या एक से अधिक क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं:

1. शासन और सार्वजनिक सेवाएँ
    - सरकारी सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता
    - डिजिटल पहुँच और सार्वजनिक कार्यालयों के साथ सहज संपर्क
    - निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी
    - कानूनी, न्यायिक और पुलिस सुधार
2. बुनियादी ढाँचे की कमियाँ
    - गतिशीलता और परिवहन
    - सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता और पहुँच
    - सड़क अवसंरचना और यातायात प्रबंधन
    - बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता
    - सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी (जैसे, इंटरनेट की सुविधा)
3. आवास और शहरी नियोजन
    - किफायती आवास
    - भीड़भाड़ वाले या खराब नियोजित शहरी क्षेत्र
    - अपर्याप्त स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ
    - पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाओं तक पहुँच
4. स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और शिक्षा
    - स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता
    - किफायती और समावेशी सेवाओं तक पहुँच
5. सुरक्षा और संरक्षा
    - कानून और व्यवस्था की स्थिति

- महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित कमजोर समूहों की सुरक्षा

6. पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

- वायु और जल प्रदूषण
- खराब अपशिष्ट निपटान
- हरित स्थानों और जैव विविधता का नुकसान
- हरित स्थान और टिकाऊ शहरी नियोजन

7. आर्थिक चुनौतियाँ

- बेरोजगारी या अल्परोजगार
- जीवन–यापन की बढ़ती लागत
- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का अभाव
- नागरिकों और उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी

8. शासन और सार्वजनिक सेवाएँ

- नौकरशाही लालफीताशाही और भ्रष्टाचार
- खराब सेवा वितरण (लाइसेंस, परमिट, आदि)
- शासन में नागरिकों की भागीदारी का अभाव

9. सामाजिक असमानता

- जाति, लिंग, नस्ल या धर्म के आधार पर भेदभाव
- सार्वजनिक सेवाओं तक असमान पहुँच
- कमजोर आबादी का हाशिए पर होना

10. डिजिटल विभाजन

- डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों तक असमान पहुँच
- सीमित डिजिटल साक्षरता
- ई–गवर्नेंस या शिक्षा जैसी ऑनलाइन सेवाओं से वंचित रहना

निबंध के सामान्य दिशानिर्देश

निबंध अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होना चाहिए। एक निबंध की लंबाई लगभग 5000 शब्द होनी चाहिए। 5500 शब्द सीमा से अधिक का निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगी को निबंध के कुल शब्दों की संख्या बतानी होगी, अन्यथा निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी निबंधों को कागज के केवल एक तरफ डबल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए और जो प्रविष्टियाँ शर्तों का पालन नहीं करती हैं उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसे 'नाम–डी–प्लम' या 'उपनाम' के तहत तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रतियोगी का पूरा नाम और पता एक अलग शीट पर उल्लिखित होना चाहिए और एक सीलबंद लिफाफे में संलग्न होना चाहिए, जिसमें बाहरी आवरण पर निम्नलिखित शिलालेख के साथ नाम लिखा होना चाहिए।

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2025, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

सभी निबंध महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110002 को स्पीड पोस्ट द्वारा और सॉफ्ट कॉपी ईमेल trgiipa@yahoo.co.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, ताकि उन तक पहुंच सके। 31 अगस्त 2025 से पहले नहीं। लिफाफे पर 'वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता–2025' अंकित होना चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

निबंध का निर्णय न्यायाधीशों के एक निकाय द्वारा किया जाएगा और न्यायाधीशों का पुरस्कार अंतिम होगा। यदि प्रस्तुत निबंधों में से कोई भी आवश्यक मानक को पूरा नहीं करता है तो संस्थान को कोई पुरस्कार नहीं देने का अधिकार सुरक्षित है। पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई भी निबंध लेखक और आईआईपीए की संयुक्त बौद्धिक संपदा बन जाएगा।

कृपया ध्यान दें: अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के इच्छुक प्रतियोगी महानिदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड़, नई दिल्ली–110002 को लिख सकते हैं।